

क्रमांक 421-ज(I)-86/13640.— श्री जवाहर सिंह, पुत्र श्री मूगे रोम, गांव रिठाऊ, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, की दिनांक 30 जून, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जवाहर सिंह की मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2883-ज-(II)-72/32282, दिनांक 29 अगस्त, 1972 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती कलावती के नाम रबी, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

सोम नाथ,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,  
राजस्व विभाग।

वित्त विभाग

(विनियम)

दिनांक 16 अप्रैल, 1986

संख्या 4/3(2)/85-2 एफ. आर.-I.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा राज्यार्थ, पंजाब सिविल सेवा नियम, जिल्द-II को आगे संशोधित करने के लिये, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम पंजाब सिविल सेवाएं, जिल्द-II (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम, 1986 कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब सिविल सेवाएं नियम, जिल्द-II (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 13.14 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखे जायेंगे अर्थात्:—
  - (i) (3)(i) सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को उसके व्यक्तिगत प्रयोग के लिये मोटरकार, या मोटर साईकल या दो पहियों वाला स्कूटर अथवा मोपिड खरीदने हेतु उसके खाते में जमा सामान्य भविष्य निधि की राशि में से लौटाई जाने वाली अग्रिम राशि की स्वीकृति दे सकता है।
  - (ii) इस प्रयोजन के लिये अभिदाता को उसकी निधि में से दी गई कोई अग्रिम राशि उस की निधि में जमा अतिशेष के 3/4 भाग अथवा यान की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।
  - (iii) यदि किसी अभिदाता ने सरकार से मोटरकार अथवा मोटर साईकल, स्कूटर अथवा मोपिड के लिये पहले ही सरकार से अग्रिम राशि (कर्ज के रूप में) प्राप्त कर ली हो, तो वह ऐसी अग्रिम राशि को ब्याज सहित, यदि कोई हो, भुगतान करने के बाद ही अपनी सामान्य भविष्य निधि से राशि निकलवा सकता है।
  - (iv) अभिदाता से अपेक्षा की जाएगी कि वह मोटरकार या मोटर साईकल या स्कूटर अथवा मोपिड को, प्रस्तावित विक्री के सम्बन्ध में विक्रेता के साथ किया गया करारनामा अथवा प्राधिकृत कम्पनी के व्यवहारी या अभिकर्ता का लिखित कथन और शपथ-पत्र प्रस्तुत करे जिसमें यह कथित हो कि उसने मोटरकार, मोटर साईकल, दो पहियों वाले स्कूटर अथवा मोपिड खरीदने के लिये इससे पहले अपनी सामान्य भविष्य निधि से कोई राशि नहीं निकलवाई है। उक्त शपथ-पत्र में उसके द्वारा यह भी कथित किया जायेगा कि क्या उसने इससे पहले इस प्रयोजन के लिये सरकार से कोई अग्रिम राशि (कर्ज के रूप में) निकलवाई थी। यदि हां तो क्या उसने अपनी सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम राशि के लिये आवेदन देने की तिथि से पहले यह राशि ब्याज सहित, लौटा दी है।

- (V) यदि अभिदाता ने मोटरकार अथवा मोटर साईकल अथवा दो पहियों वाला स्कूटर अथवा मोपिड खरीदने के लिए सरकार से कर्जा प्राप्त कर लिया है और अभी भी उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, तो कर्ज और यान की वास्तविक कीमत के बीच के अन्तर की राशि अथवा उसका खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत भाग, जो भी कम हो, उसकी सामान्य भविष्य निधि में से लौटाई जाने वाली अग्रिम राशि के नाते उसे दी जा सकेगी।

टिप्पणी:—अभिदाता जिसे इस नियम के अधीन निधि से धन निकलवाने की अनुज्ञा दी जाती है, वह राशि निकलवाने की तिथि से दो मास की अवधि के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को यान के पंजीकरण विलेख की साध्यांकित अथवा फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो इस प्रकार निकलवाई गई समूची राशि नियम 13.13 के अधीन विदित दर पर ब्याज सहित अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त एकमुश्त वापिस कराई जायेगी।

3. उक्त नियमों में, नियम 13.29 ज को लोप कर दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, अध्याय XIII परिशिष्टे "ख" में क्रमांक 2(ii) तथा ii(क) उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक तथा उनके सामने प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी. अर्थात्:—

(iii) नियम 13.14(3) के नीचे अभिदाताओं विभागाध्यक्ष नियम 13.14(3) में दी गई शर्तों को सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम राशि के अधीन रहते हुए पूरी शक्तियाँ की स्वीकृति देना।

(ख) क्रमांक 5 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।

एम० सी० गुप्ता,

सचिव, हरियाणा सरकार,  
वित्त विभाग।

## FINANCE DEPARTMENT

### (REGULATION)

The 16th April, 1986

No. 4/3(2)/85-2 FRI.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309, of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Civil Services Rules, Volume II, in their application to the State of Haryana, namely:—

1. These rules may be called the Punjab Civil Services, Volume II (Haryana Second Amendment) Rules, 1986.

2. In the Punjab Civil Services Rules, Volume II (hereinafter called the said rules), in rule 13-14 after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

3. (i) A competent authority may sanction refundable advance from the General Provident Fund to a subscriber from the amount standing at his credit in the Fund for the purchase of a motor car, or motor cycle or two wheeler scooter or a moped for his personal use.

(ii) Any sum advanced to a subscriber for this purpose from the amount in the Fund shall not exceed 3/4th of the balance at his credit in the Fund or the actual price of the vehicle, whichever is less.

(iii) If a subscriber had received a motor car or motor cycle or scooter or moped advance (in the shape of loan) earlier from the Government, he can draw the amount from his General Provident Fund only after the repayment of such an advance (Loan) along with interest, if any.

(iv) The subscriber would be required to produce an agreement with the seller or a written statement of a dealer or an agent of the authorised company in regard to the proposed sale of motor car or motor cycle or scooter or moped to the applicant as well as an affidavit stating that he had not withdrawn any sum from his General Provident Fund earlier for the purpose of purchase of motor car, motor cycle, two wheeler scooter or a moped, it shall also be stated by him in the above said affidavit whether he had drawn any advance (in the shape of loan) from Government for this purpose in the past. If so, whether it has been returned or not, along with interest, before the date of application for the advance from his General Provident Fund.

(v) If the subscriber has received loan from the Government for the purchase of a motor car or motor cycle or two wheeler scooter or moped and still his requirement is not fulfilled, then the difference of the loan and the actual price of the vehicle or 75% of his credit, whichever is less will be admissible to him from his General Provident Fund as refundable advance.

**Note :—**A subscriber who is permitted to withdraw money from the Fund under this rule, shall produce an attested or a photostat copy of the Registration deed of the vehicle to the sanctioning authority within a period of two months from the date of drawal and if he fails to do so the whole of the amount so withdrawn alongwith interest thereon at the rate prescribed under rule 13-13 shall forthwith be repaid to the Fund by the subscriber in lump sum.

3. In the said rules, rule 13-29 (H) shall be omitted.

4. In the said rules, in Annexure B, to Chapter XIII—

(a) after serial number 2 (ii) and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely :—

(iii) To sanction advance from the General Provident Fund to the subscribers under rule 13-14 (3)	Heads of Departments	Full powers subject to the conditions laid down in rule 13-14 (3)
---	----------------------	---

(b) Serial number 5 and entries thereagainst shall be omitted.

M. C. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,  
Finance Department.

#### LABOUR DEPARTMENT

The 31st March, 1986

**No. 12(14)81-1Lab.**—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958) and all others powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby exempts the establishment of the Banks specified below located in the State of Haryana, from the operation of sections 7, 8, 9, 10 and 22 of the said Act:—

- Scheduled Banks within the meaning of clause (c) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act 2 of 1934) and all other financial commercial Banks;
- Subsidiary Banks within the meaning of clause (k) of section 2 of the State Bank of India (subsidiary Banks) Act, 1959 (Act 38 of 1959) and
- All Regional Rural Banks, set up under the Regional Rural Banks Act, 1976 (Act 21 of 1976).

KULWANT SINGH,

Secretary to Government, Haryana,  
Labour and Employment Department.

श्रम विभाग

दिनांक 31 मार्च, 1986

संख्या 12(14)81-1 श्रम.—पंजाब दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 28 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 10 तथा 22 के प्रवर्तन से हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट बैंक स्थापनों को छूट प्रदान करते हैं:—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2) की धारा 2 को खण्ड ड के अर्थों में उन अनुसूचित बैंक तथा सभी अन्य वित्तपोषक वाणिज्यिक बैंक,

- (ii) भारतीय स्टेट बैंक (समभुषणी बैंक) अधिनियम, 1959 का अधिनियम 38 की धारा 2 के खण्ड "ट" के अर्थों में समभुषणी बैंक, और
- (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 21) के अधीन स्थापित सभी क्षेत्रीय बैंक।

कुलवन्त सिंह,

सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम तथा रोजगार विभाग।

#### LABOUR DEPARTMENT

#### CORRIGENDUM

The 21st April, 1986

No. 12(116)-78-2Lab.—In Haryana Government, Labour Department Notification No. 12(116)-78-2Lab, dated 18th May, 1985, under the heading "Representative of Employers" the name and designation at serial No. 2 of Shri J. S. Sehti, Personnel Manager, M/s Ballarpur Industries Limited, Yamuna Nagar shall be substituted by Shri R. L. Mehra, Personnel Manager, M/s Ballarpur Industries Ltd., Unit Shree Gopal, Yamuna Nagar.

KULWANT SINGH,

Financial Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Labour and Employment Department.

#### CORRIGENDA

Reference the notification of Haryana Government, Development and Panchayat Department issued,—vide No. DPH-EI-86/335, dated 27th February, 1986.

Please read block Naraingarh instead of block Raipur Nani in Column No. 3 against serial No. 662-A, 643-A and 494.

Reference the notification of Haryana Government Development and Panchayats Department issued,—vide No. P. S. Election-86/340, dated 21st March, 1986.

"Please read the name of Gram Panchayat Sasai-Kalirawan instead of Gram Panchayat Sasai-Bola."

S. K. SHARMA,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.

#### AGRICULTURE DEPARTMENT

The 29th April, 1986

No. 476-P.C. (Agri-II)-APO-86/715-34.—For implementation, supervision and monitoring of "Centrally Sponsored Scheme of Assistance to Small and Marginal Farmers for Increasing Agricultural Production in the State", the Governor of Haryana is pleased to constitute an Inter Departmental Coordination Committee to oversee, guide and coordinate the implementation of this programme as under :—

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Chief Secretary to Government, Haryana   | Chairman |
| 2. Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department              | Member   |
| 3. Director of Agriculture  | Do       |
| 4. Deputy General Manager, National Bank for Agriculture and Rural Development Chandigarh | Do       |

5. Managing Director,  
Haryana State Co-operative Land Development Bank,  
Chandigarh Member
6. Managing Director,  
Haryana Land Reclamation and Development Corporation,  
Chandigarh Do
7. Managing Director,  
Haryana Agro-Industries Corporation, Chandigarh Do
8. Additional Deputy Commissioners-cum-Chief Executive  
Officers, District Rural Development Agencies in the State Do
9. Joint Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department Member-Secretary

The head quarter of the committee will be at Chandigarh. The Committee will meet at least twice a year to review progress of implementation of the above scheme and oversee, guide and coordinate its implementation.

M. K. MIGLANI,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Agriculture Department.

श्रम विभाग

अदेश

दिनांक 5 मई, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/88-85/15212.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म० फरीदाबाद, मिश्रित प्रशासन फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अमर चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री अमर चन्द पुत्र, हरि राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ०वि०/अम्बाला/12-86/15218.—चूँकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि दी आफिसर इन्चार्ज सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च सेंटर, सेक्टर 27, चण्डीगढ़, 2. दी सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट, सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च फार्म, मन्सा देवी, डाकखाना मनीमाजरा, पंचकुला (अम्बाला), के श्रमिक श्री राम प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूँकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राम प्रकाश की सेवाओं समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है?

जे. पी. रतन,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम विभाग।